some difficulty in getting trained personnel.

Faicilities for production and research in the field of drugs have been developed considerably in public sector undertakings. Some firms in the private sector also have introduced facilities for research.

(d) It is proposed to create an additional capacity of 1700 admissions per annum to the degree course in Pharmacy during the Fourth Plan period. For this purpose, Central assistance is made available to State Governments and Universities for starting diploma and degree courses. In order to meet the requirements of the drug industry, manufacturing agencies have also been asked by Government to provide facilities for in-service training to trained pharmacists.

Control on Sale and Purchase of Gold

1936. Shri Atam Das: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Government for controlling the sale and purchase of gold;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government have formulated any proposal to provide alternative employment to goldsmiths who are likely to be affected as a result thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). No, Sir. No fresh proposal is under consideration.

The Gold Control Rules envisage licensing of Gold refiners and dealers in gold and ornaments and certification of the self-employed goldsmiths: detailed forms of accounts and returns have been prescribed for these persons. The Rules also prohibit possession or acquisition of primary gold by persons other than licensed dealers, refiners and certified goldsmiths. The Refineries will manufacture gold only in the form of Standard Gold Bars as prescribed. These features have the effect of indirectly controlling the sale and purchase of gold. In view of the ban on private possession of primay gold, imposed under the Defence of India (Fourth Amendment) Rules, 1966, necessary provision has been made in the Rules for the disposal of legally held primary gold during the interim period before the ban becomes absolute from 31st August, 1967.

(c) The procedure prescribed for disposal of the legally held primary gold will not adversely affect the business of goldsmiths. However, in 1963 certain schemes were formulated to rehabilitate the goldsmiths affected by Gold Control. These include financial and other assistance to goldsmiths who elected to change their occupation. Technical training and educational facilities are also given. These assistance schemes are being continued.

योजनाओं की क्रियान्विति में जनता का सहयोग

1937. श्री क० मि० मधुकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजनाओं की क्रियान्विति में ग्राम पंचायत, खण्ड तथा जिला स्तर पर लोगों का सक्रिय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो योजनाओं की क्रियान्विति में जनता का सहयोग प्राप्त करने में सरकार की उदासीनता के क्या कारण हैं ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां, सभी स्तरों पर ।

(ख) जन सहयोग सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार समिति जिसमें कई प्रमुख स्वैच्छिक

संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं ने जन सहयोग में राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किये हैं । समिति विकास कार्यक्रमों में जनता का भागीदारी की समस्याओं पर विचार करने के लिए वाद-विवाद के स्थान के रूप में भी कार्य करती है। जो मुख्य योजनाएं हाथ में ली गई हैं वे हैं :-

(1) लोक कार्य क्षेत्र (शहरी तथा ग्राम्य)

(2) योजना में रुचि पैदा करने के लिए विश्व-विद्यालयों और कालेजों में योजनागोष्ठियां ।

(3) जन सहयोग में अनुसंधान तथा मार्गदर्शी परियोजनाओं का गठन ।

(4) राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा; और

(5) तकनीकी कार्य ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन

1938. श्री क० मि० मधुकर : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भपात के बारे में कोई कानून बनाने से पहले इस बारे में अपेक्षित सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक पहलुओं पर विशेषज्ञों की राय मांगी गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीमति अमृतकौर) : (क) और (ख). गर्भपात के कानून को उदार बनाने का प्रश्न महाराष्ट्र के जन-स्वास्थ्य, विधि एवं न्याय-पालिका के भूतपूर्व मंत्री श्री शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में स्थापित एक समिति को भेजा गया था । इस समिति ने विभिन्न व्यक्तियों को एक प्रश्नावली भेजी थी, जिनमें और लोगों के अलावा, चिकित्सा, सामाजिक कानूनी, राजनैतिक तथा नैतिक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल हैं । इन सभी विशेषज्ञों द्वारा प्रकट की गई रायों पर उचित विचार करने के बाद, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसे जल्दी ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा । इस समिति की सिफारिशें पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं ।

मातातीला बांध से बिजली

1939. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को मातातिला परियोजना से बिजली देने के प्रश्न पर सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). मातातिला परियोजना से मध्य प्रदेश को बिजली सप्लाई करने के विषय पर केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से हाल ही में कोई बातचीत नहीं की है ।

दोनों राज्य सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार मातातिला से मध्य प्रदेश को आपस में तय किये गये मूल्य पर लगभग 2.5 मैगावाट बिजली दी जायेगी । इसमें से उत्तर प्रदेश 11 अप्रैल, 1965 से लगभग एक मैगावाट बिजली मध्य प्रदेश को झांसी से दे रहा है । मध्य प्रदेश ने इच्छा प्रकट की है कि उन्हें मातातिला की बिजली चार स्थानों अर्थात मातातिला, झांसी, मौरानीपुर और बांदा से दी जाये । मातातिला के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से बिजली देने के प्रस्ताव से बिजली के पारेषण पर अतिरिक्त व्यय होने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है जिस पर इस समय दोनों राज्य बिजली बोर्डों के बीच बातचीत हो रही है ।